



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2017/पौष 6, 1939

No. 487]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2017/PAUSHA 6, 1939

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 दिसम्बर, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2017-18/ 025.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15अख, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अक तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19अक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 में,-

- (I) अध्याय - VI के पश्चात् और अध्याय - VII से पूर्व, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"अध्याय - VI

निपटारे की संक्षिप्त प्रक्रिया

निपटारे की संक्षिप्त प्रक्रिया

14क. (1) अध्याय - VI में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारित (विनिर्दिष्ट) कार्यवाही (स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग) शुरू करने से पहले, बोर्ड निम्नलिखित कथित (अभिकथित) चूकों (डिफॉल्ट / व्यतिक्रमों) के संबंध में, अनुसूची-III में यथा निर्धारित फॉर्मेट में निपटारे की सूचना (नोटिस) जारी कर सकेगा, जिसमें नोटिसी से यह कहा जाएगा कि वह उस निपटारे की रकम का भुगतान करते हुए और/या उन अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) के संबंध में वचन प्रस्तुत करते हुए या उन अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) का पालन करते हुए, शुरू की जाने वाली निर्धारित (विनिर्दिष्ट) कार्यवाही (कार्यवाहियों) के संबंध में निपटारे का आवेदन दाखिल करे, जिसका (जिनका) उल्लेख निपटारे की सूचना (नोटिस) में किया जाए,-

- i. विवरणियाँ, रिपोर्ट, दस्तावेज, आदि को देरी से दाखिल करना;
- ii. देरी से प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) करना;
- iii. जिन प्रादेशिक (रीज़नल) स्टॉक एक्सचेंजों का निकास (एग्जिट) हो चुका है, केवल उन प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) न करना;
- iv. निर्धारित फॉर्मेटों में प्रकटीकरण करने में असफल रहना;
- v. कानूनी प्रावधानों की किन्हीं अपेक्षाओं का या बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करने में देरी करना;
- vi. ऐसे अन्य उल्लंघन (अतिक्रमण) [जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएँ]:

परंतु यह कि, निर्धारित (विनिर्दिष्ट) कार्यवाही (कार्यवाहियों) का निपटारा इस अध्याय के अधीन नहीं किया जाएगा, यदि बोर्ड की राय में, आवेदक तथ्यों का पूरा-पूरा और सही-सही प्रकटीकरण करने में असफल रहा हो या बोर्ड के अनुसार संतोषजनक रूप से सहयोग प्रदान करने में असफल रहा हो:

परंतु यह और कि, निपटारे की सूचना (नोटिस) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पास नोटिसी के खिलाफ की जाने वाली प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई में

परिवर्तन करने की शक्ति होगी और निपटारे की सूचना (नोटिस) नोटिसी को निपटारे की मांग करने का या किसी प्रवर्तन कार्रवाई से बचने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(2) नोटिसी निपटारे की सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से तीस कलेंडर दिनों के भीतर, -

(क) अनुसूची-I के भाग-क में निर्धारित प्ररूप (फॉर्म) में निपटारे का आवेदन दाखिल कर सकेगा, जिसके साथ अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) आवेदन फीस (जैसा अनुसूची-I के भाग-ख में उल्लेख किया हुआ है) लगाई जाएगी तथा वचन और अधित्यजन (वेवर) [जैसा अनुसूची-I के भाग-ग में उल्लेख किया हुआ है] भी लगाए जाएँगे;

(ख) निपटारे की रकम [जिसका उल्लेख निपटारे की सूचना (नोटिस) में किया जाए] प्रेषित कर सकेगा; और

(ग) अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) [जिनका उल्लेख निपटारे की सूचना (नोटिस) में किया जाए] का, यथास्थिति, पालन कर सकेगा या पालन करने का वचन दे सकेगा:

परंतु यह कि, निपटारे की सूचना (नोटिस) में उल्लिखित निपटारे की रकम की गणना में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर, नोटिसी निपटारे का आवेदन दाखिल करते समय उसमें सुधार की मांग कर सकेगा और ऐसे मामलों में बोर्ड का निर्णय (विनिश्चय) अंतिम होगा तथा रकम बोर्ड का निर्णय प्राप्त होने की तारीख से तीस कलेंडर दिनों के भीतर प्रेषित की जाएगी:

परंतु यह और कि, बोर्ड ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध (रिकॉर्ड) किए जाएँ, निपटारे का आवेदन दाखिल करने के संबंध में, उस निपटारे की रकम को प्रेषित करने के संबंध में और/या उन गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) में से किसी शर्त आदि की बाबत वचन प्रस्तुत करने के संबंध में या उन गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) में से किसी शर्त आदि का पालन करने के संबंध में और समय प्रदान कर सकेगा (अधिक से अधिक पंद्रह कलेंडर दिनों का और समय प्रदान कर सकेगा), जिसका (जिनका) उल्लेख निपटारे की सूचना (नोटिस) में किया जाए।

(3) बोर्ड, निपटारे की सूचना (नोटिस) में उल्लिखित निपटारे की रकम के प्रेषण से और गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों), यदि कोई हों, के संबंध में प्रस्तुत किए गए वचन से या गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) के पालन से संतुष्ट हो जाने पर, विनियम 15 के अधीन निपटारे का आदेश पारित करेगा।

14ख. अध्याय-VI में और विनियम 14क में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख को लंबित निर्धारित (विनिर्दिष्ट) कार्यवाहियों के संबंध में, बोर्ड ऐसी कार्यवाहियों की बाबत विनियम 14क के उप-विनियम (1) के अधीन निपटारे की सूचना (नोटिस) जारी कर सकेगा और ऐसे मामलों में विनियम 14क में दी हुई प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

स्पष्टीकरण. - इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित (विनिर्दिष्ट) कार्यवाही को तब तक शुरू की गई और लंबित कार्यवाही नहीं माना जाता, जब तक कि बोर्ड उस मामले की सूचना उस प्राधिकारी को न भिजवा दे, जो ऐसी कार्यवाहियों का संचालन करेगा।

14ग. इन विनियमों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ नोटिसी इस अध्याय के अधीन निपटारे का आवेदन दाखिल नहीं करता या निपटारे की रकम प्रेषित नहीं करता और/या बोर्ड के अनुसार संतोषजनक रूप से अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) का पालन नहीं करता या निपटारे का आवेदन वापस ले लेता हो, वहाँ निर्धारित (विनिर्दिष्ट) कार्यवाहियाँ, यथास्थिति, शुरू की जा सकेंगी या जारी रखी जा सकेंगी, और ऐसे नोटिसी को केवल उन्हीं कार्यवाहियों की बाबत निपटारे का आवेदन दाखिल करने की अनुमति होगी, जो, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी (अडजूडिकेटिंग ऑफिसर) या बोर्ड के समक्ष पूरी (समाप्त) हो जाने के पश्चात् न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) के समक्ष चल रही (लंबित) हों।”

(II) अनुसूची-II में, अध्याय I में, -

(क) मद (12) का लोप हो जाएगा;

(ख) मौजूदा मद (13), मद (12) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगी।

(III) अनुसूची-II के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

“ अनुसूची-III

(विनियम 14क देखें)

प्ररूप

तारीख

.....

पता

विषय: के मामले में निपटारे की सूचना (नोटिस)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने
 के मामले में अन्वेषण (इन्वेस्टीगेशन) / निरीक्षण / जाँच /
 जाँच-पड़ताल के दौरान *पहली नज़र में ही (प्रथमदृष्ट्या)* यह पाया है कि आपने प्रतिभूति
 विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन (अतिक्रमण) किया है:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

जो निष्कर्ष सामने आए हैं, उनके उद्धरण संलग्न हैं।

2. उपरोक्त के मद्देनज़र, आपके खिलाफ (*संबंधित प्रावधान,
 जिनके अधीन कार्यवाहियाँ शुरू की जा सकती हैं या जारी रखी जा सकती हैं*) के अधीन
 कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं।

3. शुरू की गई (की जाने वाली) उपरोक्त कार्यवाहियों का निपटारा, तभी किया जा सकेगा,
 जब इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने की तारीख से 30 कलेंडर दिनों के भीतर, भारतीय
 प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का
 निपटारा) विनियम, 2014 के अधीन निपटारे का आवेदन दाखिल कर दिया जाए और उसके
 साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का
 निपटारा) विनियम, 2014 के (प्रावधान) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति
 और विनियम बोर्ड (सेबी) को रु. की निपटारे की रकम प्रेषित कर दी
 जाए और निम्नलिखित गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) का पालन कर लिया जाए :

(i)

(ii) [*यदि कोई दूसरी शर्तें आदि हों, तो कृपया उनका उल्लेख
 करें।*]

4. यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारे की रकम प्रेषित नहीं की जाती है और/या
 गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) में से किसी शर्त आदि का पालन नहीं किया जाता है या
 उनके पालन के संबंध में वचन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो बोर्ड आपके खिलाफ कानूनी

प्रावधानों के अनुसार कोई निर्धारित (विनिर्दिष्ट) कार्यवाहियाँ शुरू कर सकता है या उन्हें जारी रख सकता है।

इस सूचना (नोटिस) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पास आपके खिलाफ शुरू की गई (की जाने वाली) कार्यवाहियों और लगाए गए (जाने वाले) आरोपों में परिवर्तन करने का अधिकार आरक्षित है, और यह सूचना (नोटिस) निपटारे की मांग करने का या बोर्ड द्वारा शुरू की गई किसी कार्रवाई से बचने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. यदि निपटारे का आवेदन दाखिल नहीं किया जाता है या निपटारे की रकम प्रेषित नहीं की जाती है और/या अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) के संबंध में वचन प्रस्तुत नहीं किया जाता है या बोर्ड के अनुसार संतोषजनक रूप से अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि (निबंधनों) का पालन नहीं किया जाता है या निपटारे का आवेदन वापस ले लिया जाता है, तो निर्धारित (विनिर्दिष्ट) कार्यवाहियाँ, यथास्थिति, शुरू की जा सकेंगी या जारी रखी जा सकेंगी, और आपको केवल उन्हीं कार्यवाहियों की बाबत निपटारे का आवेदन दाखिल करने की अनुमति होगी, जो, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी (अडजूडिकेटिंग ऑफिसर) या बोर्ड के समक्ष पूरी (समाप्त) हो जाने के पश्चात् न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) के समक्ष चल रही (लंबित) हों।

नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

संलग्नक: उपरोक्तानुसार"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./358/17]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/37/50 द्वारा, 9 जनवरी 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 तत्पश्चात् :-
 - (1) 15 सितम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/08/1491, द्वारा
 - (2) 29 अगस्त 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/010, द्वारा
 - (3) 27 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/036, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th December, 2017

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**(SETTLEMENT OF ADMINISTRATIVE AND CIVIL PROCEEDINGS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2017**

SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/025.—In exercise of the powers conferred under section 15JB of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, section 23JA of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and section 19-IA of the Depositories Act, 1996 read with section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Second Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014,—

(I) After Chapter VI and before Chapter VII, the following Chapter shall be inserted, namely—

"CHAPTER VIA**Summary Settlement Procedure****Summary Settlement Procedure**

14A. (1) Notwithstanding anything contained in Chapter VI, before initiating any specified proceeding the Board may issue a notice of settlement in the format as specified in Schedule-III, calling upon the noticee to file a settlement application in respect of the specified proceeding(s) to be initiated, upon payment of the settlement amount and/or furnishing an undertaking in respect of other non-monetary terms or compliance with other non-monetary terms, as may be specified in the settlement notice in respect of the following alleged defaults,—

- i. Late filing of returns, report, document, etc.;
- ii. Delay in making disclosures;
- iii. Non-disclosure in relation to companies exclusively listed on regional stock exchanges which have exited;
- iv. Failure to make disclosures in the prescribed formats;
- v. Delay in compliance of any of the requirements of law or with directions issued by the Board;
- vi. Such other violations as may be determined by the Board.

Provided that, the specified proceeding(s) shall not be settled under this Chapter, if in the opinion of the Board, the applicant has failed to make a full and true disclosure of facts or failed to co-operate to the satisfaction of the Board:

Provided further that, notwithstanding anything contained in the notice of settlement, the Board shall have the power to modify the enforcement action to be brought against the noticee and the notice of settlement shall not confer any right upon the noticee to seek settlement or avoid any enforcement action.

(2) The noticee may within thirty calendar days from the date of receipt of the notice of settlement,—

- (a) file a settlement application in the Form specified in Part-A of the Schedule-I alongwith non-refundable application fee as specified in Part-B and the undertakings and waivers as specified in Part-C of the Schedule-I;
- (b) remit the settlement amount as specified in the notice of settlement; and
- (c) comply or undertake to comply with other non-monetary terms as specified in the notice of settlement, as the case may be.

Provided that, in case of any discrepancy in calculation of settlement amount specified in the notice of settlement, the noticee may seek rectification of the same at the time of filing the settlement application and in such cases the decision of the Board shall be final and remittance shall be done within thirty calendar days from the date of receipt of the decision of the Board.

Provided further that, the Board may for reasons to be recorded, grant extension of time not exceeding a further period of fifteen calendar days for filing of the settlement application, remittance of the settlement amount and/or furnishing an undertaking in respect of any of the non-monetary terms or compliance with any of the non-monetary terms specified in the notice of settlement.

(3) The Board upon being satisfied with the remittance of settlement amount and undertaking furnished in respect of non-monetary terms or compliance with non-monetary terms, if any specified in the settlement notice, shall pass an order of settlement under regulation 15.

14B. Notwithstanding anything contained in Chapter VI and in regulation 14A, with respect to specified proceedings pending as on the date of commencement of this Chapter, the Board may issue a notice of settlement under sub-regulation (1) of regulation 14A in respect of such proceedings and in such cases the procedure specified in regulation 14A shall apply mutatis mutandis.

Explanation. - For the purposes of this Chapter, it is clarified that a specified proceeding is not deemed to be initiated and pending, unless the Board has communicated the matter to the authority who shall conduct such proceedings.

14C. Notwithstanding anything contained in these regulations, where a noticee does not file a settlement application under this Chapter or remit the settlement amount and/or comply with other non-monetary terms to the satisfaction of the Board or withdraws the settlement application, the specified proceedings may be initiated or continued, as the case may be and such a noticee shall only be permitted to file a settlement application in respect of proceedings pending before a Court or tribunal after conclusion of proceedings before the Adjudicating Officer or the Board, as the case may be."

(II) In Schedule II, in Chapter I, -

- (A) Item 12 shall be deleted;
- (B) Existing item (13) shall be renumbered as item (12).

(III) After Schedule II, the following Schedule shall be inserted, namely,-

"Schedule III

(See regulation 14A)

Form

To

Date

.....

Address

Sub: Notice of settlement in the matter of

Securities and Exchange Board of India (SEBI) during the investigation/ inspection/ inquiry/ examination in the matter ofhas *prima facie* observed that you have violated the following provisions of the securities laws:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

Extracts of the findings are enclosed.

2. In view of the aforesaid you are liable to be proceeded against under(***relevant provisions under which the proceedings may be initiated or continued***)

3. The aforesaid proceedings (to be) initiated may, be settled and disposed of upon filing of a settlement application under the SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings)

Regulations, 2014 alongwith remittance of a settlement amount of Rs.to SEBI in terms of (provision) of SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 within 30 calendar days from the date of receipt of this notice and upon complying with the following non-monetary terms:

(i)

(ii) (*please specify any other terms, if any*)

4. If remittance of the settlement amount is not made and/ or any of the non-monetary terms are not complied or undertaken to be complied within the specified time, the Board may initiate or continue any specified proceedings against you in accordance with law.

Notwithstanding anything contained in this notice, the Board reserves the right to modify the proceedings and charges (to be) brought against you and this notice shall not confer any right to seek settlement or avoid any action initiated by the Board.

5. If the settlement application is not filed or the settlement amount is not remitted and/or undertaking in respect of other non-monetary terms is not furnished or other non-monetary terms are not complied to the satisfaction of the Board or the settlement application is withdrawn, the specified proceedings may be initiated or continued, as the case may be and you shall be permitted to file a settlement application only in respect of proceedings pending before a Court or tribunal after conclusion of proceedings before the Adjudicating Officer or the Board, as the case may be.

Name, designation and signature

Encl: As above"

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./358/17]

Footnote:

1. The SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 were published in the Gazette of India on January 09, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/37/50.
2. The SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 were subsequently amended on:-
 - (1) 15th September, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/08/1491.
 - (2) 29th August, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. LAD-NRO/GN/2016-17/010.
 - (3) 27th February, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. LAD-NRO/GN/2016-17/036.